

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत बोले 'एमएलए-एमपी घोड़े-गधे की तरह बिक रहे',

कहा- भ्रष्टाचार ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, कानून-व्यवस्था बहाल; पेंशन, पानी संकट और एलिवेटेड रोड को लेकर भी साधा निशाना

भीलवाड़ा फोकस @ जोधपुर ।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को जोधपुर में भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, पेंशन योजनाओं, पानी संकट और लोकतांत्रिक मूल्यों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। गहलोत ने कहा कि देश में आज जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त आम हो गई है और 'एमएलए-एमपी ऐसे बिक रहे हैं जैसे घोड़े, गधे, भैंस और बकरी बिकते हैं।' उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में भ्रष्टाचार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है।

जोधपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि ऑपरेशन लोटस को लेकर उनका मुंह न खुलवाया जाए। उन्होंने कहा कि जनता को

इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, अन्यथा लोकतंत्र का भविष्य संकट में पड़ सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हत्या, दुष्कर्म और फायरिंग जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जोधपुर में हाल ही में हुई फायरिंग की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों ने पीड़ितों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और गोलीबारी की, जो प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था का उदाहरण है।

गहलोत ने भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर राज्य में भ्रष्टाचार की शिकायतें होती हैं, लेकिन राजस्थान में वर्तमान सरकार के दौरान हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आम लोगों को न्याय और प्रशासनिक कार्यों के लिए भी पेंशन



होना पड़ रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद किए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में उदयपुर और जालोर के दौरे के दौरान उन्हें ऐसे बुजुर्ग मिले जिन्हें तीन-चार महीने से पेंशन नहीं मिली है। उन्होंने दावा किया कि लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा

एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने स्वयं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड का निर्णय उनकी पहल पर हुआ था और उन्होंने कभी भी परियोजना में बाधा नहीं डाली।

गहलोत ने जोधपुर भाजपा में कथित गुटबाजी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पार्टी के विधायक स्वयं कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं और यह स्थिति सरकार की अंदरूनी कमजोरी को दर्शाती है।

पेयजल संकट पर उन्होंने कहा कि जोधपुर सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर मुद्दे को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दे रही है, जबकि आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

टंकी के बालाजी के पास आलू से भरा ट्रोला पलटा, सड़क पर बिखरी बोरियां, मची अफरा तफरी, ड्राइवर चोटिल



भीलवाड़ा फोकस @ भीलवाड़ा

पुनित चपलोत

शहर के कोटा बाईपास स्थित टंकी के बालाजी के पास मंगलवार सुबह एक आलू से भरा ट्रोला अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रोले में लदी आलू की बोरियां सड़क पर बिखर गईं। गनीमत रही कि दुर्घटना के समय आसपास कोई वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार ट्रोला अजमेर की ओर से भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी की तरफ आ रहा था। इसी दौरान टंकी के बालाजी के निकट चालक का वाहन पर

नियंत्रण बिगड़ गया और ट्रोला सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया तथा सड़क पर आलू की बोरियां फैल गईं।

सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। बाद में क्रैन की सहायता से पलटे हुए ट्रोले को सीधा कराया गया। दुर्घटना में चालक को मामूली चोटें आईं। यह हादसा एक बार फिर कोटा बाईपास पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही को लेकर सवाल खड़े करता है। सुबह के समय यातायात कम होने के कारण बड़ा नुकसान टल गया, लेकिन यदि यह दुर्घटना व्यस्त समय में होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी।

यमुना का पानी मिलने की राह हुई आसान, एमओए के अहम बिंदुओं पर बनी सहमति

दिल्ली में राजस्थान-हरियाणा और केंद्र की अहम बैठक, शेखावाटी सहित प्रदेश के लाखों लोगों को मिलेगा लाभ

K भीलवाड़ा फोकस @ जयपुर/नई दिल्ली

राजस्थान को यमुना जल उपलब्ध कराने की दिशा में मंगलवार को बड़ा कदम आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ यमुना जल परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंतिम रूप दिया गया।

बैठक के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यमुना जल परियोजना के तहत पानी को पारंपरिक नहरों के बजाय पाइपलाइन नेटवर्क

के माध्यम से पहुंचाने का प्रस्ताव है, जिससे जल संरक्षण के साथ वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी और व्यापक होगी।

किशाऊ बांध परियोजना पर भी बनी सहमति

बैठक में किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री पाटिल ने बताया कि परियोजना से जुड़े छह राज्यों के अधिकांश मुद्दों का समाधान हो चुका है और शीघ्र ही इससे संबंधित एमओए पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण होने पर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा सहित अन्य राज्यों को भी पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा।

शेखावाटी क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी परियोजना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यमुना जल परियोजना राजस्थान, विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी तथा लाखों लोगों के जीवन स्तर



में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र और हरियाणा सरकार के सहयोग से परियोजना को जल्द धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दशकों से लंबित परियोजनाओं की गति मिल रही है और राज्यों के बीच जल विवादों का सकारात्मक समाधान निकल रहा है। राजस्थान लंबे समय से अपने हिस्से के यमुना जल की मांग कर रहा था और अब इस दिशा में ठोस प्रगति दिखाई दे रही है।

किसानों, उद्योगों और आमजन को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि परियोजना के लागू होने के बाद राजस्थान को अपने हिस्से का पानी मिलने लगेगा, जिससे किसानों को सिंचाई, उद्योगों को जल उपलब्धता और आमजन को पेयजल के क्षेत्र में बड़ा

लाभ मिलेगा। साथ ही प्रदेश में जल प्रबंधन व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

हर व्यक्ति तक पानी पहुंचाना लक्ष्य : सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हर व्यक्ति तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रेणुका, लखवार और किशाऊ बांध परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के लोगों को लाभ मिलेगा। बैठक में वर्षा जल को संरक्षित कर राजस्थान तक पहुंचाने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में केंद्र सरकार, राजस्थान के जल संसाधन विभाग तथा हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जनहित के भूमि आवंटन प्रकरणों को मिलेगी गति, मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने की विस्तृत समीक्षा

शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और शहरी विकास से जुड़े मामलों पर चर्चा, पात्र प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

भीलवाड़ा फोकस @ जयपुर ।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जनहित एवं विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से मंगलवार को शासन सचिवालय में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, औद्योगिक विकास एवं सार्वजनिक उपयोग की संस्थाओं के लिए रियायती दरों पर भूमि आवंटन से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा की गई। समिति ने पात्र मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा जनोपयोगी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत तथा

नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े संस्थानों के भूमि आवंटन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। समिति ने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए ताकि आमजन को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सके। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर भी बैठक में विशेष चर्चा हुई। समिति ने चिकित्सा संस्थानों में राज्य सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं, विशेषकर मा योजना एवं आरजीएएस के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए अधिकाधिक लोगों तक इनका लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर समिति ने



शहरी सेवा अभियान के तहत पट्टों के वितरण, लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा नागरिकों को राहत पहुंचाने वाले प्रावधानों के प्रभावी उपयोग पर बल दिया। इसके साथ ही औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के भवन निर्माण से जुड़े मामलों में प्रक्रियाओं के सरलीकरण, किशतों में भुगतान और ग्रेस पीरियड जैसी सुविधाओं पर भी सकारात्मक चर्चा की गई।

बैठक में नगरीय कराधान एवं शुल्क निर्धारण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पारदर्शी और व्यावहारिक प्रणाली विकसित करने के लिए आवश्यक

प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विभिन्न संस्थागत, शैक्षणिक एवं सामाजिक उपयोग के भूमि आवंटन मामलों में आरक्षित दरों से छूट के प्रकरणों पर भी विचार किया गया।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जनोपयोगी परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाकर आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

'भीलवाड़ा फोकस'

अपने शहर और गाँव के समाचार, सूचनाएँ, सार्वजनिक घोषणाएँ या विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए संपर्क करें।

Mo.- 8696795959
Bhilwarafocus@gmail.com



भीलवाड़ा की बात, फोकस के साथ

